समीक्षा सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है और तदनुसार निर्यात के बारे में निर्णय किया जाता है।

(ग) जी हां। भारतीय रूई निगम और कुछ राज्य सहकारी समितियां/फैडरेशन रूई के निर्यात में लगे हुए हैं।

(घ) तथा (ङ) एक विवरण संलग्न है : [देखिए परिशिष्ट CXXXVI अनुपत्र संख्या 11]

(च) 1985–86 मौसम के लिए सरकार ने कपास की विभिन्न किस्मों की न्यूनतम समर्थन कीमतें पहले ही घोषित कर दी हैं।

कपास उत्पादन

1071. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कपास उत्पादन के राज्य वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और देश में कपास की मांग कितनी है;

(ख) पिछले वर्ष लम्बे रेशे और छोटे रेशे की कपास का उत्पादन देश की मांग से कितना अधिक या कम हुआ;

(ग) कपास उत्पादकों को पिछले वर्ष अपनी उपज के लिए प्रति क्विंटल क्या मूल्य दिया गया ; और

(घ) इस वर्ष कपास का बाजार भाव क्या है और कपास उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) चालू रूई सीजन के दौरान संभावित रूई का उत्पादन 95.6 लाख गांठों के आसपास होने का अनुमान है। इस वर्ष के दौरान घरेलू खपत 91.6 लाख गांठों के आसपास होने का अनुमान है।

(ख) गत वर्ष के दौरान, एक स्तर पर उत्पादन 92 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया गया। इस आकलन के आधार पर लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे की किस्मों की 4.72 लाख गांठों का अधिशेष और मध्यम किस्म की लगभग 2 लाख गांठों की गिरावट की संभावन थी। बाद में कुल फसल के अनुमान को संशोधित किया गया जिसे 101.5 लाख गांठ कर दिया गया। परन्तु किस्मों का कोई अलग अलग ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) गत रूई सीजन के दौरान रूई उपजकर्ताओं को भारतीय रूई निगम द्वारा दी गई कपास की प्रति क्विंटल औसत कीमतें विभिन्न किस्मों के लिए 476 रु० प्रति क्विंटल से 900 रु० प्रति क्विंटल के बीच रहीं।

(घ) 15–11–85 को यथास्थिति कपास की बाजार कीमतें विभिन्न किस्मों के लिए 677 रु0 प्रति क्विंटल से 3961-रु० प्रति क्विटल के बीच रही। भारतीय रूई निगम को, जहां भी कहीं कीमतों के न्यूनतम समर्थन स्तर से नीचे आने की प्रवृत्ति हो, कीमत समर्थन कार्यक्रम चलाने के लिए निदेश दिया गया है। सरकार ने वह रूई भी निर्यात के लिए रिलीज की है जिसे हमारी घरेलू आवश्यकताओं से अधिशेष समझा जाता है।

Supply of pig iijon to Gujarat by SAIL

1072. SHRl VITHALBHAI MOTI-RAM PATEL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the Steel Authority of India Limited has failed to supply pig iron as per demand and requirement of engineering industry in Gujarat;

(b) whether it 4g. also a fact that due to the failure of the Authority the State Government has requested the Central Government to allow it to import pig iron; and

(c) if so, what is the reaction of the Central Government thereto?